बारे में सरकारी नीति की घोषणा शीघ्र होनी चाहिए ।

जहां तक मूल्य-वृद्धि का सवाल है, अभी श्री शंकर घोष ने अपने भाषण में कहा कि देश की आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी हो गई, यदि वित्त मन्त्री जी, वह जो हर साल उल्लेख दिया जाता था—स्टेट आफ इकानामी—उसकी रिपोर्ट देते तो पता लगता अपने देश की आर्थिक स्थिति क्या है । उन्होंने महंगाई के बारे में कहा कि हमने महंगाई पर रोक लगा दी लेकिन 1974 में जो मूल्य तालिका थी वह इस साल फिर मूल्य तालिका हो गई । इस चुनाव में कई जगह पोस्टरें लगी हुई थीं—देखो भाई पुराना खेल. चौदह रुपए कड़वा तेल । यानी खाने का तेल फिर 12–14 रु० किलो हो गया ।

इसी तरह से कपड़े को ले लीजिए । माननीय चट्टोपाध्याय साहब ने चुनाव के पूर्व जो सस्ते कपड़े थे गरीबों के लिए, उस पर 33 प्रतिशत मूल्य-वृद्धि की आज्ञा दे दी । क्यों दिया, किस परिस्थिति मे दिया, किन मजबूरियों में दिया ? आम लोगों में चर्चा है कि चुनाव के लिए धन एकत्रित करने के लिए ऐसा किया गया । तो मैं सुझाव दूंगा कि यदि किसी आर्थिक मजबूरी के कारण भी किया गया, यानी सरकार को धन चाहिए या आर्थिक दृष्टि से है, तो भी मैं यह चाहूंगा कि जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके धनार्जन का जो स्रोत है, उसका अकाउन्ट प्रतिवर्ष सरकार को मांगना चाहिए—कितना चन्दा उनको मिलता है, चन्दा कहां से आता है और उस चंदे को कैसे खर्च किया जाता है । यह सरकारी कानून बना कर सभी राजनैतिक दलों को मजबूर करें कि वे अपने खर्च का ब्यौरा, जिस तरह से इनकम टैक्स को आम जनता देती है सालाना, उसी तरह पोलिटिकल पार्टीज भी दें और उनको सख्ती से लागू किया जाए जिससे कि अनावश्यक किसी के प्रति सन्देह या एक दूसरे के ऊपर लांछन न लगे, रयूमर्स पैदा न हों और सारी बातें साफ हो जाएं ।

इन शब्दों के साथ मैं इसका स्वागत करता हूं ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sardar Amjad Ali. He is not here. Mr. Swaminathan, not here.

We adjourn to meet at 2 P.M. After that, the Finance Minister will start his reply.

The House then adjourned for lunch at four minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock,

Mr. Deputy Chairman in the Chair.

STATEMENTS BY MINISTERS

I. Changes in policy re. Posts and Telecommunications Services.

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडेस) : महोदय, संचार मन्त्री के पद का भार ग्रहण करने के उपरान्त मैं सदन को नीति सम्बन्धी कुछ परिवर्तनों की मोटी रूपरेखा से अवगत कराना चाहता हूं जिन्हें लागू करने का मेरा विचार है ।

यद्यपि मैंने डाक और तार विभाग में जिन बातों को प्राथमिकता अब तक दी गयी है उनका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है तथापि इस समय मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं डाक और दूर-संचार सेवाओं का गांवों में विस्तार करने पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं ।

पहाड़ी, जनजातियों और पिछड़े हुए इलाकों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय ा और इन्हे विशेष प्राथमिकता दे दी जायगी । इस समय हमारे देश के 6.8 लाख गांवों

[श्री जार्ज फर्नांडिस]

में से 31890 (4.63 प्रतिशत) गांवों में दैनिक डाक योजना का विस्तार नहीं है। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि इस वर्ष देश के सभी गांवों में दैनिक डाक वितरण योजना लागू हो जाय। गांवों में और छोटे कस्बों में 100 से अधिक डाकघर की इमारतें बनाई जायेंगी। इस से वहां काम करने वाले कर्मचारियों को काम करने की अधिक सहूलियत होगी और डाक घर में जो जनता जाती है उस को बेहतर सुविधायें प्राप्त होंगी। अब तक ग्रामीण पोस्टमैनों और विभागेतर डिलीवरी एजेंटों द्वारा रजिस्ट्री वस्तुओं की बुकिंग की सुविधा सिर्फ महाराष्ट्र डाक सर्किल में उपलब्ध थी। अब इस सुविधा का दूसरे सर्किलों के डाकघरों में भी विस्तार किया जायगा और देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध हो जायगी।

जहां तक दूर संचार सेवा का संबंध है, ब्लाक मुख्यालय और इस से ऊपर के स्तर के स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की धुरी है। इस की संख्या 7653 है। अब तक ऐसे 1127 स्थानों में टेलीफोनों की सुविधायें नही हैं और 968 स्थानों में तार की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि आगामी वित्तीय वर्ष में इन सभी स्थानों में यह सभी सुविधायें उपलब्ध हो जायें।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम दिल्ली को चार राज्यों की राजधानियों, बंगलौर, भुवनेश्वर, कलकत्ता और कोहिमा को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एस०टी०डी०) के जरिये आज जोड़ने जा रहे हैं।

देश के दूसरे दो महानगर बंबई और कलकत्ता भी आज रात से एस टी डी के जरिये जुड़ जायेंगे। आज ही दूसरे मार्गों जैसे भिवानी, अम्बाला और दिल्ली में भी ये सेवायें आज से दी जायेंगी। उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा के जरिये दूर संचार सेवा ज्यादा तेजी से मिलती है और इस प्रकार देश की एकता मजबूत होती है।

देश के 96 नगरों में टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की गयी हैं। इन में से 61 समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और बाकी समितियों का इस साल समाप्त हो जायेगे। हम चाहते हैं कि टेलीफोन सलाहकार समितियों के समूचे दर्शन और मूलाधार पर अगले तीन महीनों में पुनरीक्षण किया जाय।

मैं विदेश संचार सेवा के विकास को भी अधिक महत्व दे रहा हूं अब देहरादून में दूसरा उपग्रह भूमि स्टेशन बन गया है। इसलिये अब हम ऐसी स्थिति में हो गये हैं कि दूसरे बहुत से देशों से संचार संपर्क कर सकते हैं। इस वर्ष इंटेलसेट के भारत महानगर में उपग्रह की ओर उन्मुख 39 देशों में से 36 देशों से संपर्क स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है।

मेरी उत्कट अभिलाषा है कि हम दूर संचार के साज सामान को जिस गति से अपने देश में बना रहे हैं उस में और तेजी लायें ताकि हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति में आत्मनिर्भर हो जायें। इस दिशा में इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्री लिमिटेड, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड और हमारे डाक तार कारखाने अच्छा काम कर रहे है। मेरी कोशिश यह होगी कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इन इकाईयों में काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूरों के बीच अधिक से अधिक सहयोग बढ़े।

पिछले समय में हमारे स्टाक को जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा उस से मैं अवगत हूं। उन के साथ सद्व्यवहार और न्याय किया जाय, इस दृष्टि से मैंने

यह फैसला किया है कि 1968 और 1974 में डाक तार विभाग के हड़तालों के कारण जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाहियां की जा रही थी उन्हें समाप्त किया जाय। इन हड़तालों के कारण कर्मचारियों के ऊपर जो अयोग्यतायें लगाई गई थीं उन सब को दूर कर दिया जायगा और उन को उन के मूल स्थान, पोजेशंस फिर से मिल जायेंगे।

मेरे इस मंत्रालय के कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभाग के अधिकारी और डाक–तार कर्मचारी संघों के नेता मुझ से मिले है। अधिकारियों और डाक–तार कर्मचारियों ने जो उत्साह दिखलाया है उस से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। इन सभी ने बेहतर और अधिक विनीत सेवायें देने के कार्य में मेरी सहायता करने का वचन दिया है। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि निकट भविष्य में ही इस के अच्छे नतीजे प्राप्त करने में हमें सहायता मिलेंगी।

II. Derailment of Mangalore Madras Express at sevur Stafe of Southern Railway on March 30, 1977

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): Sir, I regret very much to inform this House that at about 12.50 hrs. on 30-3-1977, while No. 28 Up Mangalore-Madras Express, with a load of 16 coaches and hauled by a diesel engine, was running through Sevur station on *Katpadi-Arkonam broad gauge double* line section on Madras division of Southern Railway, 9 coaches marshalled 5th to 13th from the train engine derailed, of which six coaches capsized. The Up line was obstructed but the Down line remained free for through traffic.

As a result of the accident, 6 persons are reported to have been killed, 17 sustained grievous injuries and another 33 received minor injuries so far. On receipt of information about the accident, Assistant Medical Officer, Katpadi proceeded to the site immediately. Medical Relief Trains from Madras and Jolarpettai and road ambulances were rushed to the site. General Manager and Chief Medical Officer, Southern Railway accompanied by other Heads of Departments, Divisional Supermtendent, Madras and other Divisional Officers rushed to the site by road to supervise relief and rescue operations. All the *injured persons were taken to* Vellore by road ambulances and admitted in Mission Hospital and the Government Hospital. *Ex-gratia* payment to the next of kin of the dead and to the injured has been arranged.

Additional Member Mechanical, Railway Board has proceeded to the site of accident by air.

The Additional Commissioner of Railway Safety is likely to commence his statutory inquiry into this accident on 1-4-1977.

One more information is to be added. This is the latest information. With the death of 2 more persons in Government Hospital, Vellore, today morning, the number of dead is now 8 and the number of grievously injured persons is 15.

THE BUDGET (GENERAL) 1977-78—GENERAL DISCUSSION—Contd.

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): Sir, I have listened with great nterest to the speeches made by honourable Members and I wish to assure them that their comments as well as suggestions will receive my fullest attention when I take up the task of making the Budget for 1977-78. This Government has been in power only for a few days and has, therefore, not had any time to work out a programme of action which it will implement in the coming years.